अनुलग्नक–2

वस्तुस्थिति नोट –डीएमआईसीप्रोजेक्ट

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर पहला गलियारा था जिसकी घोषणा 2007 में की गई थी जिसमें पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. नोड/सिटीप्रोजेक्ट:

1. धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर), गुजरात:

- डीएसआईआर की योजना लगभग 920 वर्ग किमी क्षेत्र में बनाई गई है और डीएसआईआर में विकसित किया जाने वाला क्षेत्र छः (6) टाऊनप्लानिंग में बंटा है अर्थात टीपी स्कीम 1 टू टीपी स्कीम 6
- सभी डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के समंवय द्वारा कार्यावन्यन करने के लिए संपूर्ण डीएसआईआर के लिए प्रोग्राम मैनेजर नियुक्त किए गए है
- चूंकि संपूर्ण आधारभूत गतिविधियों विकसित किए जाने का कार्य एकसाथ नहीं किया जा सकता है, इसलिए चरणबद्ध तरीका अपनाया गया है और टीपी-2(पूर्व) और टीपी-2 (पश्चिम), 152 वर्ग किमी वाले क्षेत्र में टाऊनप्लानिंग स्कीम-2 हेतु विस्तृत मास्टर योजना एवं प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां शुरु की गई थी और कार्य पूरा हो गया है
- इंफोर्मेशन और कॉम्यूनिकेशन (आईसीटी) मास्टर प्लानिंग पूरी हो गई है
- एनआईसीडीआईटी द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधित्व और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट आथोरिटी द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व में धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई है।
- राज्य सरकार ने 30.27 वर्ग किमी भूमि एसपीवी को अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी ने समतुल्य 1745.54 करोड़ रुपए की इक्विटी जारी कर दी है।
- डीएसआईआर के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी है
- आर्थिक मामलों सं◌बंधीमंत्रिमंडलसमिति (सीसीईए) ने पांच पैकेजों में बंटे 2784.82 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक की स्थितिनिम्नानुसार है:

  - सड़क और सेवा ठेके (1734 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां जारी है।
  - एबीसीडी बिल्डिंग ठेके (72.31 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। क्यूब कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड चुना गया बोलीदाता है और कार्या पूरा हो गया है।
  - जल शोधन संयंत्र ठेके (90 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एसपीएमएल चुना गया बोलीदाता है और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां जारी है।
  - मलजल उपचार संयंत्र ठेके (54 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां जारी है।
  - सेंट्रल एफ्फलुएंट ट्रीटमेंटप्लांट(160 करोड़ रुपए)के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटीचुना गया बोलीदाता है और कार्यान्वयन संबंधी पूरे जोरों पर है।

- एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त 2019 को अपनी बैठक में एसपीवी प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 4.33 वर्ग किमी के अंतरण को अनुमोदन दिया और एनआईसीडीआईटी ने 250 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की

- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और 1450 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश के साथ टाटा केमिक्लस, टोरेंट पॉवर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड को 152.71 एकड़ भूमि के 03 प्लाट आबंटित किए गए है।

2. <u>शेन्द्रेबिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया(एसबीआईए), महाराष्ट्र</u>

- संपूर्ण शेन्द्रे (8.39 किमी) और बिडकिन (32 वर्ग किमी) के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य पूरा हो गया है;
- सभी डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के समन्वय द्वारा कार्यावन्यन करने के लिए संपूर्ण डीएसआईआर के लिए प्रोग्राम मैनेजर नियुक्त किए गए है
- एनआईसीडीआईटी द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधित्व और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलडेवलपमेंटकोरपोरेशन द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के बीच"औरंगाबादइंडस्ट्रियलटाऊनशिप लिमिटेड" नामक नामक संयुक्त उपक्रम निगमित किया गया है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा एआईटीएल को स्पेशलप्लानिंगआथोरिटी के रूप में नामित किया गया है
- शेन्द्रे और बिडकिनइंडस्ट्रियलएरियादोनों के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी है
- राज्य सरकार ने शेन्द्रा इंडस्ट्रियलएरिया के लिए 8.39 वर्ग किलोमीटर और बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 13.76 वर्ग किलोमीटर भूमि एसपीवी को अंतरित की है। एनआईसीडीआईटी द्वारा भी समतुल्य 602.80 करोड़ रुपए और 1149.90 करोड़ रुपए की इक्विटी जारी की गई है।
- शेन्द्रा इंडस्ट्रियलएरिया के लिए आर्थिक मामलों सबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1533 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित कर दिया है। विभिन्न पैकेजों में से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:

  - सड़क, नालियों, पुलियों, जल आपूर्ति, मलजल एवं उर्जा प्रणाली के लिए ईपीसी दे दिया गया है (656.89 करोड़ रुपए)। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए बोलीदाता है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां लगभग पूरी होने वाली है।
  - ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए ईपीसी (69.45 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पाटिल कन्सट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चुने गए बोलीदाता है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है।
  - जिला प्रशासन भवन के लिए ईपीसी (129 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए बोलीदाता है और कार्य हो गया है।
  - मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य एफ्फुलेएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ईपीसी (72.52 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पस्सवंट एनर्जी चुने गए बोलीदाता है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है।
  - लैंडस्केपिंग और जल सिंचाई कार्यों के लिए ईपीसी (112 करोड़ रुपए)। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए बोलीदाता है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है।
  - इंफोर्मेशन एंड कॉम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी (आईसीटी) मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्यों हेतु ईपीसी (142 करोड़ रुपए). हनीवेल चुना गया बोलीदाता है और क्रियान्वयन गतिविधियां प्रगति पर है।

- शेन्द्रा के लिए भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में हयोसंग (100 एकड़) सहित 160.33 एकड़ माप के 58 प्लाट आबंटित किए गए है। अन्य प्लाट छोटी तथा मध्यम उपक्रमों को बांटे गए है। कुल प्रतिबद्ध निवेश 4700 करोड़ रुपए है।
- माननीय प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर, 2019 को परियोजना राष्ट्र को समर्पित की
- बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 6414.21 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना पैकेज को अनुमोदित कर दिया है। चरण -1 (10.16वर्ग किमी) में विभिन्न ईपीसीपैकेजों में हुई प्रगति निम्नानुसार है:
- एलएंडटी को चरण-। अर्थात 10.16 वर्ग किमी में सड़क, भूमिगत सुविधाओं के लिए ईपीसी ठेकेदार (1223 करोड़ रुपए) नियुक्त किया गया है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है।
- आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्य (81.90 करोड़ रुपए) के लिए केईसी को नियुक्त किया गया है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है।

3. <u>ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट:</u>

- विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना गतिविधियों घटकों की विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य पूरे हो गए है
- एनआईसीडीआईटी द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधित्व और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के बीच डीएमआईसी इंटीग्रेटे डइंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड" नामक नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई है।
- प्रोजेक्ट एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा भी समतुल्य 617.20 करोड़ रुपए की इक्विटी जारी गई है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी है
- मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के लिए डिजाइन और विशिष्टियों को अंतिम रुप देने के लिए इंफोर्मेशन और टेक्नोलोजी कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है।
- विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए ईपीसी (426 करोड़ रुपए) दे दिए गए हैं। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए बोलीदाता है और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है।
- 121 करोड़ रुपए की लागत वाले आंतरिक उर्जा अवसंरचना कार्यों के लिए ठेकेदार के रूप सिमंस को नियुक्त किया गया है और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है।
- 156 करोड़ रुपए की लागत वाले ट्रांसमिशन नेटवर्क से संबंधित कार्य को उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कोरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में हैयर (123.7 एकड़) को 152 एकड़ माप के चार प्लाट आबंटित किए गए हैं। कुल प्रतिबद्ध निवेश 3670 करोड़ रुपए है।

4. <u>इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रमउद्योगपुरी' प्रोजक्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश</u>

- परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है।
- एनआईसीडीआईटी द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधित्व और एमपीट्रेड एंड इन्वेस्टमेंटफेसिलेशनकोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व में डीएमआईसीइंटीग्रेटिडटाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई।

- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1100 एकड़ भूमि अंतरित की और एनआईसीडीटी ने 55.93 करोड़ रुपए की समतुल्यइक्विटी जारी की।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी है
- विभिन्नअवसंरचना कार्यों(332 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दी गई है। एसपीएमएल चुने गए बोलीदाता है औरकार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां पूरी हो गई है।
- पानी की लाइन बिछाने (129 करोड़ रुपए) और पॉवर ट्रांसमिशन लाइन (40 करोड़ रुपए) बिछाने का कार्य दे दिया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और अमूल को 12 एकड़ माप वाला प्लाट आबंटित किया गया है। कुल प्रतिबद्ध निवेश 200 करोड़ रुपए है।

5. <u>खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, राजस्थान</u>

- समग्र शाहजहांपुर-नीमराणा-बेहरोड़ अरबन कॉम्पलेक्स के भाग के रूप में मास्टरप्लान को अधिसूचित किया गया है
- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चरण–I के विकास अर्थात लगभग 14 वर्ग किमी के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है

6. <u>जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियलएरिया,राजस्थान</u>

- मास्टरप्लान अधिसूचित किया गया है
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस दे दी है
- राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए कहा गया है

7. <u>दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र</u>

- दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कार्य आगे बढ़ रहे है और विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य किया जा रहा है जिसके अक्टूबर, 2019 में पूरा होने की संभावना है।
- डीपीआईए के चरण-1 के लिए संपूर्ण भूमि अर्थात 3000 हेक्टेयर राज्य सरकार के कब्जे में है।

ख. <u>संपर्कतृता परियोजनाएं:</u>

1. <u>धोलेरा, गुजरात में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट</u>

- धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस प्राप्त हो गई है
- नागर विमानन मंत्रालय ने परियोजना के लिए ''सैद्धांतिक'' क्लीयरेंस दे दी है।
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने डीपीआर को अनुमोदन दे दिया है और परियोजना में 51 प्रतिशत इक्विटी ली है।
- एएआई, गुजरात सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट निष्पादित किया गया है
- एनआईसीडीआईटी ने अपनी इक्विटी (16 प्रतिशत) के रूप में 19.85 करोड़ रुपए को जारी किया है

2. भीमनाथ धोलेरा रेल लाइन प्रोजेक्ट, गुजरात

- रेल मंत्रालय के गैर-सरकारी मॉडल के अनुसार परियोजना को डीआईसीडीएल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा
- परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है

3. अहमदाबाद और धोलेरा के बीच एमआरटीएस, गुजरात:

- राज्य सरकार द्वारा एमआरटीएस के लिए डीपीआर तैयार और अनुमोदित की गई
- परियोजना को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जीका रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है
- एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के आरओडब्ल्यू के भाग के रूप में एमआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
- एनएचएआई द्वारा अहमदाबाद और धोलेरा के बीच एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और भूमि अधिग्रहण पूरा होने वाला है

4. मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, हरियाणा:

- ''डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड'' नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी को निगमित किया गया है।
- दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन सहित राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित किया गया है।
- प्रोजेक्ट के चरण-I के लिए भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है।
- प्रोजेक्ट को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जीका स्पेशल रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है

5. भिवाडी,राजस्थान में ग्रीनफील्ड इंटरनेशल एयरपोर्ट:

- नागर विमानन मंत्रालय ने साइट क्लीयरेंस दे दी है
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन पूरा हो गया है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंसप्राप्त की जा रही है

ग. लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स:

1. नांगल चौधरी में इंटीग्रेटिडमल्टीमॉडललॉजिस्टिक्सहब

- ''डीएमआईसी हरियाणा मल्टीमॉडललॉजिस्टिक्सहबप्रोजेक्टलिमिटेड'' नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई
- राज्य सरकार द्वारा मास्टरप्लान योजना को अनुमोदन दे दिया गया है
- परियोजना के लिए महेन्द्रगढ़ जिले में लगभग 886 एकड़ भूमि की पहचान की गई है और 639 एकड़ भूमि प्रोजेक्टएसपीवी को अंतरित कर दी है
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी और बाद में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने अनुमोदन दे दिया है।

- डीएफसीसीआईएल ने प्रोजेक्टसाइट को संपर्कत्ताउपलब्ध कराने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दे दिया है
- प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण क्लीयरेंसप्राप्त कर ली गई है
- राज्य सरकार को शेष भूमि प्राप्त करने के लिए अधिग्रहण तेज करने का अनुरोध किया गया है।

2. <u>दादरी में मल्टीमॉडललॉजिस्टिक्सहब (एमएमएलएच) और ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के बोरकी में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच):</u>

- एमएमएलएच के साथ-साथ एमएमटीएचप्रोजेक्ट का कार्यान्वयन इंटीग्रेटिडइंडस्ट्रियलटाउनशिपप्रोजेक्ट के लिए एसपीवी करेगी
- डीएफसीसीआईएल ने प्रोजेक्टसाइट को संपर्कत्ताउपलब्ध कराने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दे दिया है
- राज्य सरकार के पास 84% भूमि कब्जे में है और शेष भूमि शीघ्रता से अधिगृहीत की जा रही है
- एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त 2019 को अपनी बैठक में परियोजना के प्रस्ताव पर विचार किया और सीसीईए से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परियोजना की सिफारिश की है

3. <u>साणंद, गुजरात में मल्टीमॉडललॉजिस्टिक्स पार्क</u>

- मास्टरप्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है
- प्रस्तावित परियोजना के लिए संपर्कत्ता योजना तैयार की गई है और इसे राज्य सरकार, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया एवं रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
- राज्य सरकार ने भूमि की पहचान कर ली है जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोरपोरेशन के कब्जे में है
- एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को अपनी बैठक में एसएचए एवं विशेष प्रयोजन कंपनी के निर्माण की स्वीकृति दे दी है

घ. <u>अन्य परियोजनाएं</u>

1. <u>मॉडल सौलर परियोजना, नीमराणा, राजस्थान:</u>

- नीमराणा, राजस्थान में मॉडल सौलर पॉवर परियोजना औद्योगिक डीजल जनरेटरों के साथ सौलर पॉवर के एकीकरण के लिए (बैकअप सुविधा के रूप में) प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से विचार किया गया था। स्मार्ट माइक्रो ग्रिड के साथ एकीकृत 6 मैगावाट सौलर पीवी और 2 मैगावाट डीजल जनरेटर सेट वाली परियोजना नीमराणा इंडस्ट्रियल पार्क में स्टेट ग्रिड और जापानी इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को स्वच्छ, स्थायी, नवीकरण योग्य उर्जा की आपूर्ति कर रही है।
- 5 मैगावाट वाला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और 24 जुलाई, 2015 से पॉवर ग्रिड को फीडिंग देनी शुरू कर दी है
- 1 मैगावाट वाला प्रोजेक्ट 10 जुलाई, 2017 से शुरू हो गया है और इसकी उर्जा को मिकुनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जा रहा है

2. <u>लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस प्रोजेक्ट:</u>

- लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक में कंटेनर कार्गो मूवमेंट का पता लगाने, एक सिंगल विंडो में वास्तविक समय पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों (पत्तन, सीमा शुल्क, रेल गाड़ियां, आईसीडी आदि) की मौजूदा आईटी सिस्टम को एकीकृत करने पर विचार किया गया था
- 1 जुलाई, 2016 से जेएनपीटी पर परिचालन शुरू हो गया है

सेवा अखिल भारतीय स्तर पर सभी बड़े और कुछ छोटे पत्तनों पर परिचालन में है और 17 सितंबर, 2019 तक 18,436,002 कंटेनरों को टैग/डिटैग किया गया है।